

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियाँ को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 25

जुलाई 1990

50 पैसे

पूँजीवादी शब्दजाल

भारत में पूँजी के नुमाइन्दे शब्दों के खेल में एकमर्त है । अग्रेजी का शानक तबक के ऊपरी हिस्से की काम-काज की भत्ता होना इस खेल में उनके बड़े काम की चीज है । फरीदाबाद में मजदूरों के खिलाफ पूँजी के नुमाइन्दों द्वारा अपने शब्दजाल के इस्तेमाल के दो उदाहरण हाल ही में हमारे सामने आये हैं ।

ईस्ट इन्डिया कॉटन में उभरते मजदूर विरोध को कुचलने के लिये वहाँ की मैनेजमेंट ने दिसम्बर 89 में पावरलूम में मजदूरों के एक सामुहिक कदम के खिलाफ एक्शन ले कर कुछ मजदूरों को सस्पेंड किया था । छह महीने तक घरेलू जाँच क नाटक के बाद मैनेजमेंट ने सस्पेंड वर्कर्स के साथ नरमी बरती है—मैनेजमेंट कहती है कि वह निलम्बित मजदूरों को डिसमिस कर सकती थी पर वह नरमी बरतने हुये उन मजदूरों को डिसचार्ज कर रही है । ईस्ट इन्डिया की पावरलूम के सस्पेंड मजदूरों को इस प्रकार मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया है । वैसे, डिसमिस और डिसचार्ज के महीन भेद समझाने के लिये पूँजीवादी विद्वान आपको तत्पर मिलेंगे पर अगर आपको आधिकारिक फैसला चाहिये तो इन्तजार कीजिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहाँ पर लेबर कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुये पहुँचा एक केस डिसमिस बनाम डिसचार्ज पर फैसले का इन्तजार कर रहा है ।

डिसमिस-डिसचार्ज से भी महीन भेद वाले शब्द एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रही है । एस्कोर्ट्स में मजदूर अब ओवरटाइम काम नहीं करते बल्कि ड्यूटी के बाद वर्कर ओवरस्टे करते हैं । एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट के ओवरटाइम और ओवरस्टे शब्दों में वेहद महीन भेद दिखाना किसी अफलातून पर छोड़िये, एस्कोर्ट्स मजदूरों के लिये तो इन शब्दों में इतना फर्क है कि इनके बीच से हाथी गुजर सकता है—ओवर टाइम के लिये डबल रेट से पेमेंट होती थी जब कि ओवरस्टे के लिये सिंगल रेट से पैसे दिए जाते हैं। दरअसल ओवरटाइम के लिए डबल रेट से भुगतान का पूँजीवादी कानून काफी पुराना है । इस पूँजीवादी कानून को फरीदाबाद की अधिकतर मैनेजमेंट्स निर्लज्जता से तोड़ती हैं—आमतौर पर आठ घण्टे ओवरटाइम को रजिस्टर में चार घण्टे चढ़ा कर चार घण्टे के लिये डबल रेट से पेमेंट करके इस पूँजीवादी कानून की भरपाई कर दी जाती है । पर एस्कोर्ट्स एक जानी-मानी कम्पनी है और उसमें मिडिल मैनेजमेंट स्तर के जाने लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को ऐसी खुली धोखाधड़ी अब रास नहीं आती । फिर भी एस्कोर्ट्स में ओवरटाइम काम करवाना है और पैसे भी मजदूरों को कम ही देने हैं—क्या करे ? मैनेजमेंट में बड़ी-बड़ी डिग्री लिए बैठे साहब लोगों ने राह निकाली—यूनियन के साथ मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट की है कि एस्कोर्ट्स में ओवरटाइम काम नहीं होगा, ड्यूटी समाप्त हो जाने के बाद जिन मजदूरों को काम के लिए रोका जायेगा वे ओवरस्टे कर रहे होंगे और इसके लिये उन्हें सामान्य काम की तरह सिंगल रेट से पेमेंट की जायेगी । पर हाँ, ऐसी एग्रीमेंट चूँकि खुलेआम पूँजीवादी कानून के खिलाफ है इसलिए यह विचारियों और आकाशों के बीच जबानी जमा-खर्च मात्र है । एस्कोर्ट्स के जो भी मजदूर इस पूँजीवादी शब्दजाल को लेबर डिपार्टमेंट में चैनेन्ज करें वे यह समझ कर करें कि उन्हें लेबर डिपार्टमेंट के मन्थली ले कर कुम्भकर्णी नदी का स्वागत कर रहे लोगों को जगाने के प्रयास करने होंगे ।

मजदूरों को पूँजी के नुमाइन्दों की नींद में खलल डालने के प्रयास अवश्य करने चाहिये पर यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पूँजीवादी व्यवस्था में दरअसल चित्त भी और पट भी पूँजी के नुमाइन्दों की होती है । यह इसलिए है कि मजदूरों की राह क्रांति की राह है ।

—0—

सरकारी नौकरी

यहाँ वर्कशापों/दुकानों पर काम करने वाले मजदूर फैक्ट्री की नौकरी के लिये लड़ते हैं । प्रायवेट लिमिटेड कारखानों के मजदूर लिमिटेड कनसर्न में काम के लिए ललायित रहते हैं । और सब मजदूर परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए बेताब रहते हैं । खराब वर्किंग कंडीशनों और अन्य परेशानियों से जूझते सरकारी उद्यमों के वर्कर भी मन ही मन नौकरी के पक्की होने और रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे का हिसाब लगा कर सन्तुष्ट होने की कोशिश करते हैं । यह सही है कि वर्कशाप के वर्कर से लिमिटेड कम्पनी का वर्कर बेहतर पोजीशन में है पर कुल मिलाकर देखें तो पतनशील पूँजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के इस दौर में किसी भी मजदूर द्वारा इस व्यवस्था में सन्तुष्ट होने की कोशिश भ्रम पालने से अधिक कुछ नहीं है । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम सरकारी नौकरी की डगमग हकीकत की एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे ।

आइये पहले कुछ उदाहरण लें ।

अमरीकी-मोडल वाले देश ब्राजील के राष्ट्रपति ने 11 जून 90 को तीन लाख साठ हजार सरकारी वर्करों की छंटनी लिस्ट जारी करने की प्रतिज्ञा की थी । सरकार द्वारा उठाये जाने वाले इस कदम के खिलाफ ब्राजील में 11 जून से बीस लाख मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी । हड़ताल के जोर पकड़ते जाने के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा ढीली पड़ती गई । 16 जून को जा कर राष्ट्रपति ने 75 हजार सरकारी वर्करों की छंटनी लिस्ट जारी की और बाकी को आहिस्ता-आहिस्ता करके पाँच साल में काम से निकालने का इशारा किया । इस पर बिचौलिए सक्रिय हो गये हैं पर मजदूरों की हड़ताल के फैलने और तीखा होने के आसार हैं । और ब्राजील के हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी का कारण कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है—ब्राजील का राष्ट्रपति तो तीन लाख साठ हजार सरकारी नौकरियाँ इसलिये खत्म करना चाहता है ताकि सरकारी खर्च में कुछ कटौती की जा सके । और सरकारी खर्च में कटौती जरूरी है ताकि ब्राजील की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था सम्भाली जा सके ।

लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सम्भालने के लिए ही इंग्लैंड की प्रधान-मन्त्री थैचर ने डोल-नगाड़ों के साथ सरकारी संस्थाओं का थोक में प्रायवेट करण किया—प्रायवेटकरण की आड़ में इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सरकारी वर्करों की छंटनी की । लेकिन ऐसा करने के बावजूद इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था अब फिर लड़खड़ाने लगी है । इससे थैचर का प्रधानमन्त्री पद खतरे में पड़ गया है—नई तीन-पाँच के लिए पूँजी का ब्रिटिश धड़ा नये जादुगर नेता की तलाश में है ।

पूर्वी यूरोप के देशों में दिवालिएपन के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की कोशिश में नकली कम्युनिस्टों ने अपने नकाब तक उतार फेंके हैं । पोलैंड-हंगेरी-रोमानिया आदि में पूँजीवादी एकतन्त्र की जगह पूँजीवादी जनतन्त्र की धमाचौकड़ी में छंटनी किये गये सरकारी वर्कर लाखों बेरोजगारों के रूप में अचानक इन कुलटाओं के गर्म से टपक पड़े हैं ।

इस दौर की बड़े पैमाने की और वह भी एकमुश्त सरकारी वर्करों की छंटनी करने की बाजी रूस सरकार जीतती लगती है । पूँजीवादी जनतन्त्र के डमरू की ताल पर तत्काल छंटनी किए जाने वाले बीस लाख सरकारी वर्करों के नरमुन्डों की माला डाल कर ताँडव के लिए उत्सुक गोर्बाचोव आधुनिक शिव के खिताब का प्रबल दावेदार है । बीस लाख सरकारी वर्करों की तत्काल छंटनी के लिए रूस सरकार भी ब्राजील-इंग्लैंड आदि

(शेष अगले पेज पर)

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना । 2. पूँजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियाँ के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टों बनाने के काम में हाथ बटाना । 3. भारत में मजदूरों का क्रांतिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना । 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना ।

उनक, संगठन और सघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत के लिये बेभिकक मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे ।

की सरकारों की तर्ज पर दलील दे रही है—इस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, उसे बचाने के लिए बलि जरूरी है।

भारत में भी जब-तब कोई न कोई मन्त्री सरकारी खर्च में कटौती की बकालत करता रहता है। सरकारी संस्थाओं के प्रायवेटरण की आवश्यकता की सुगवुगाहट भी अब यहाँ होने लगी है। पर पूँजीवादी जनतन्त्र का नाटक इस समय यहाँ उभ नाजुक स्थिति में है कि “लोकप्रिय” होने की मन्त्री होड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी वर्कर्स की छंटनी वाले “अलोकप्रिय” कदम के लिये कोई नेता-मन्त्री इस समय सुलकर सामने नहीं आ रहा। पर यह टेम्परेरी स्थिति है। पूँजीवादी जनतन्त्र के इस अजबूबे में भी अर्थव्यवस्था का बढ़ता संकट विभिन्न फ़िस्म की, खास करके हिन्दूवादी पूँजीवादी एकतन्त्रीय शक्तियों को मजबूत कर रहा है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सम्भालने के लिए झटके का रूप और समय तय होने वाली बात ही बाकी बची है।

और बात ऐसी नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर दुनियाँ में ऐसा संकट पहली बार आया हो। पीछे मुड़कर 1919 में जर्मनी आदि पर निगाह डालिये चाहे 1945 में जापान आदि पर, नजारा यही देखने को मिलेगा। पतनशील पूँजीवादी व्यवस्था के बड़े संकट के फलस्वरूप 1914 में छिड़े पूँजीवादी विश्वयुद्ध में ढाई करोड़ लोग मारे गये तो 1939 में छिड़े ऐसे ही युद्ध में पाँच करोड़ लोगों का कत्ल हुआ। और जो बच गए थे उनकी चमड़ी तक पूँजीवादी संकट की भेंट चढ़ी। 1919 में और फिर 1945 में भी यूँ-भर नोटों के बदले मुट्ठी में सच्ची वाला फ़िल्मी गाना हकीकत था। लाखों की बचत और पेंशन तब कौड़ियों में बदल दी गई थी—चैन से बुढ़ापा काटने की सोच रहे रिटायर हुए लोगों को दर-दर की ठोकर खानी पड़ी थी। मरने के लिये जिन्हें भरती किया गया था पर जो फिर भी बच गये थे उन्हें तथा युद्ध के दौरान दिन-रात जिन्हें काम करने को मजबूर किया गया था उन लाखों स्त्री-बच्चे-पुरुष मजदूरों को ठोकर मार कर बेरोजगारों के रूप में सड़कों पर धकेल दिया गया था। और इस पूँजीवादी अफ़रा-नफ़री ने 1919 के बाद पूँजीवाद के हिटलरी जुनून को जन्म दिया था तो 1945 के बाद एटम बमों से लैस मानव जाति को नष्ट करने की तैयार पूँजीवादी गिराही को खड़ा किया है।

कहने का मतलब यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था की पतनशीलता के इस दौर में इस व्यवस्था को बड़े संकट का जब भी झटका लगता है, सरकारी नौकरी और पेंशन आदि पानी का बलबुला साबित होती है। दुनियाँ-भर में यह बार-बार देखने में आ रहा है कि सरकारें और उनके वादे ताश के पत्तों के महल हैं, जो कोई इन पर भरोसा करके चैन की नींद सोने की आशा करते हैं वे मूर्खों के लोक में विचरण करते हैं। 1938 में अपने रोजमर्रा के जीवन में मगन पीढ़ी को अहसास तक नहीं था कि पूँजीवादी व्यवस्था के संकट ने उसे मौत के कगार पर ला खड़ा किया है। 1939 से 1945 तक की पूँजीवादी मार-काट में कत्ल हुए पाँच करोड़ लोग सपने में तलवार भाँजते से अपनी मौत के मुँह में धकेल दिये गए थे।

आज हालात 1914 या 1938 से भी विकट हैं। ऐमे में अन्धी सामाजिक शक्तियों के हाथों सम्पूर्ण मानव जाति के विनाश की सम्भावना पर आँख मूंद लेना हमारी अपनी बरबादी की न्यौता देना है। पूँजीवाद के संकट के बढ़ते जाने के साथ उसमें सन्तुष्ट रहने के लिए तिनके ढूँढना बिल्ली को देख कर कबूतर द्वारा आँख बन्द कर लेने के समान है।

इसलिए आइये थोड़ा यह समझने की कोशिश करें कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है का क्या मतलब है, देश को मजबूत करने का आज क्या अर्थ है। पूँजीवाद में उत्पादन मानवों की जरूरत को ध्यान में रख कर नहीं किया जाता बल्कि मंडी में बिक्री के लिये प्रोडक्शन होता है। बुनियादी तौर पर आज उत्पादन देशों के आधार पर संगठित है और मार्केट है विश्व मंडी। ऐसे में किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का मतलब यह है कि उस देश का प्रोडक्शन विश्व मंडी में अन्य देशों के उत्पादन के मुकाबले टिक नहीं पा रहा। यानि, उस देश में पैदा किया गया सामान अन्य देशों की तुलना में महंगा है। और चूँकि अर्थव्यवस्था आज भी सामाजिक जीवन की धुरी है इसलिये ऐसे में किसी देश को मजबूत करने का पहला मतलब है उस देश में प्रोडक्शन की लागत को कम करना। लेकिन उत्पादन खर्च कम करने का अर्थ है कम मजदूरों से कम मजदूरी पर अधिक प्रोडक्शन लेना। इसलिये किसी देश को मजबूत करने का मतलब यह है कि उस देश के मजदूर कम तनखा लें और ज्यादा काम करें। देशभक्ति का मजदूरों के लिये मतलब यह है कि वे पूँजीवादी गुटों को होड़ में “अपने” पूँजीवादी गुट की बेदी पर अपना रक्त चढ़ावें।

हर देश में पूँजीवादी शिक्षा और पुलिस-फौज वाले पूँजीवादी डण्डों से मजदूरों को बलिदान की दिशा में हाँक कर देश को मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं। पर होड़ चूँकि विश्व मंडी के दायरे में है इसलिए हर देश द्वारा कम मजदूरों से कम तनखा पर ज्यादा काम लेने का नतीजा यह है कि दुनिया-भर में मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है और साथ ही साथ विश्व मंडी में पूँजीवादी गुटों की होड़ और तेज हो रही है। पूँजीवादी व्यवस्था का संकट है कि बढ़ता ही जा रहा है।

असल में मंडी के लिये उत्पादन की जगह अब प्रोडक्शन को मानवों के उपयोग के लिये संगठित करना जरूरी हो गया है। इसके लिये विश्व मंडी के स्थान पर विश्व मानव समुदाय की स्थापना आवश्यक हो गई है। कम्युनिस्ट क्रान्ति अब जरूरी हो गई है अन्यथा विश्व मंडी की प्रतियोगिता के साथ चलती फौजी होड़ एटम बमों के घमाकों के साथ मानव जाति के विनाश की राह पर बढ़ेगी।

आज प्रायवेटरण की लाख चर्चा हो पर हकीकत यह है कि अब दुनिया में प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी उद्यमों में हो रहा है। और कितना ही आड़ा-तिरछा हो कर यह क्यों न चले, प्रोडक्शन में सरकारी क्षेत्र का वजन बढ़ेगा ही। हर देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी दबाव बढ़ता जायेगा। इसलिये सामाजिक जीवन में सरकारी वर्कर्स का महत्व आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अतः क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन की सफलता के लिए उसमें सरकारी क्षेत्र के मजदूरों का हिस्सा लेना बहुत जरूरी हो गया है। और फिर, सरकारी वर्कर्स के अपने हित माँग करते हैं कि वे पूँजीवादी रेत की दीवार पर टेक लगाने की बजाय क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन में आगे बढ़ कर हिस्सा लें। वर्कशाप का हो चाहे फैक्ट्री का, प्रायवेटर उद्यम का हो चाहे सरकारी का, हर मजदूर का फर्ज है कि वह क्रान्ति की राह को पहचाने और उस पर चलने की कोशिश करे।

—0—

अगर एकजुट हो जायें.....

आमतौर पर पूँजीवादी प्रचार मजदूरों से जुड़े आन्दोलनों की खबरें बहुत कम करके देता है—तोड़-मरोड़ तो वह करता ही है। दिक्कत यह भी है कि आज सचेत व संगठित क्रान्तिकारी आन्दोलन बहुत ही कमजोर है जिसकी वजह से पूँजीवादी नकाब व तोड़-मरोड़ से निपटना बहुत मुश्किल है। हमारी अपनी कमजोरी ऊपर से..... फिर भी, नजर डालिये मई 90 के कुछ समाचारों पर और सोचिये।

- दिल्ली के मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में मजदूरों और मैनेजमेन्ट के गुंडों के बीच टकराव।
- गाजियाबाद के साहिवाबाद क्षेत्र की फैक्ट्रियों में मजदूरों के बढ़ते गुस्से से मैनेजमेन्ट चिन्तित।
- तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र की चार कपड़ा मिलों में हड़ताल।
- दक्षिण कोरिया में हड़तालों की लहर।
- निकारागुआ में 15 मई को हड़ताल से काम-काज ठप्प।
- महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले की फैक्ट्रियों में मजदूरों का गुस्सा भड़क रहा है। मजदूरों के खिलाफ और सख्ती के लिए मैनेजमेन्टों के प्रति-निधियों की भूख हड़ताल।
- बिहार में हजारीबाग जिले की कोयला खदानों में मजदूरों का जुझारू संघर्ष।
- अर्जेंटीना में सात लाख मजदूरों की 13 से 20 मई तक हड़ताल।
- यूनान में दस लाख मजदूरों ने 22 मई को हड़ताल की।
- रोमानिया में दस हजार जहाजरानी और गोदी मजदूर हड़ताल पर।
- पोलैंड में रेलवे मजदूरों की हड़ताल।

यह सही है कि क्रान्तिकारी विकल्प के अभाव में मजदूरों के असन्तोष को अक्सर पूँजीवादी गुट एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार फर्जी हड़तालों भी एक हकीकत है लेकिन आज दुनिया-भर में मजदूरों का बढ़ता असन्तोष मुख्य बात है। और, जगह-जगह भड़क रहे मजदूरों के गुस्से को एकजुट करके मजदूरों व समाज के अन्य हिस्सों के दुख-दर्द की जननी इस पूँजीवादी व्यवस्था को हमलों का निशाना बनाने की जरूरत है। इसके लिये सचेत तौर पर क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन को दुनिया-भर में पुनः संगठित करने की जरूरत है। तो आइये, मिल कर कम्युनिस्ट आन्दोलन की राह के रोड़ों को दूर करें

दुनियाँ-भर में मजदूरों का मुखर हो रहा असन्तोष अगर एकजुट हो जाये तो पूँजीवाद को अजायबघर की चीज बनाने में देर नहीं लगेगी।

—X—